

न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर  
पीठासीन अधिकारी : सुनिता चौधरी, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 67/2025

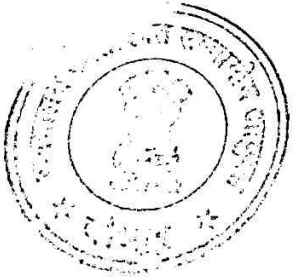
अपीलान्त

बनाम

रेस्पोडेन्टस

1. ठाकर सिंह पुत्र नगसिंह  
निवासी- स्वरूपनगर तहसील  
शिव जिला बाडमेर।

1. उत्तमसिंह पुत्र नगसिंह
2. गोपालसिंह पुत्र जवारसिंह
3. गोपीदेवी पत्नी गोपालसिंह
4. जालमसिंह पुत्र अलससिंह
5. झवरसिंह पुत्र अलससिंह
6. बाबूसिंह पुत्र अलससिंह
7. रामकंवरी पत्नी अलसिंह
8. लखसिंह पुत्र आम्बसिंह
9. विजयसिंह पुत्र अलससिंह
10. समधाकंवर पत्नी अलससिंह
11. हरकंवर पुत्री अलससिंह
12. जेठाराम पुत्र वगताराम  
निवासीगण- धारवीकला  
तहसील शिव।
13. राजस्थान सरकार जरिये  
तहसीलदार, शिव, बाडमेर।



अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधि. 1956 विरुद्ध  
आदेश दिनांक 03.02.2025 को उपखण्ड अधिकारी शिव जिला  
बाडमेर के द्वारा राजस्व प्रकरण संख्या 114/2022 अनवान  
ठाकरसिंह बनाम तहसीलदार, शिव वगैराह में पारित किया गया।

उपस्थिति:—

1. श्री रेखाराम चौधरी, विद्वान अधिवक्ता अपीलान्तस् की ओर से।
2. श्री गिरधरसिंह भाटी, अधिवक्ता रेस्पो0संख्या 1, 3 से 6, 7 व 9 से 11 की ओर से।
3. श्री नवलसिंह दहिया, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 13 की ओर से।
4. रेस्पो0 संख्या 2 एवं 8 बावजूद तामीली के अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक: 6 मई, 2026

1. अपीलान्त ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी शिव जिला बाडमेर के द्वारा  
राजस्व प्रकरण संख्या 114/2022 अनवान ठाकरसिंह बनाम तहसीलदार, शिव

*du*  
सुनिता चौधरी  
जोधपुर

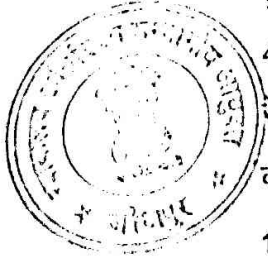
वगैराह में पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 03.02.2025 के विरुद्ध यह राजस्व अपील दिनांक 28.02.2025 को न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई।

2. अपीलान्ट के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित है। दौरान सुनवाई अपीलान्ट के अभिभाषक ने यह कथन किया कि अपीलान्ट के द्वारा रेस्पोजेन्ट्स के विरुद्ध अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अन्तर्गत धारा 131, 136 राज0 भू राजस्व अधिनियम के तहत एक प्रार्थना पत्र पेश करते हुए कथन किया कि ग्राम स्वरूपनगर तहसील शिव में ख0सं0 558/372 रकबा 6.4750 हैक्टर भूमि अपीलान्ट की खातेदारी की स्थित है जिसके पडौस में रेस्पोजेन्ट्स संख्या 2 का खेत ख0सं0 560/372, पश्चिम और दक्षिण की तरफ रेस्पोजेन्ट्स संख्या 3 व 4 का खसरा संख्या 567/372 व रेस्पोजेन्ट्स संख्या 5 से 12 का खेत ख0सं0 556/372 आया हुआ है तथा अपीलान्ट अपनी उक्त खातेदारी भूमि जो कि आवंटित शुदा है, जिसकी पट्टा डायरी व नक्शा प्रति वक्त आवंटन के समय अपीलान्ट को जारी की थी तथा आवंटन के अनुसार भौतिक कब्जा दिलाया गया था। मगर बाद में रेस्पोजेन्ट्स यदि वादग्रस्त भूमि के सेढा पडौसियों ने माठ को तोड़ दिया तथा तरमीम के अनुसार कब्जा काश्त को भी बदल दिया, जिससे व्यथित होकर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तरमीम दुरुस्ती हेतु आवेदन पेश किया था। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा उक्त प्रस्तुत प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया गया तथा अप्रार्थीगण को तलब किया गया। तत्पश्चात दोनों पक्षों को सुनने के उपरान्त अपीलान्ट के उक्त आवेदन को अस्वीकार करने का अपीलाधीन आदेश दिनांक 3.2.2025 को पारित कर दिया गया जो निरस्त करने योग्य है।

3. अपीलान्ट के अभिभाषक ने यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने वादग्रस्त भूमि के सेढा पडौसियों के जवाब और रेस्पोजेन्ट्स के हक में पक्षपात रवैया अपनाकर अपीलान्ट के आवेदन को खारिज कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त अपीलान्ट को सही ढंग से सुना ही नहीं गया और पटवारी की ओर से पेश मौका रिपोर्ट को आधार मानकर तथा बिना युक्तियुक्त अवसर प्रदान व प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तों का उल्लंघन करते हुए अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया जो काबिल निरस्ती है। अपीलान्ट वक्त आवंटन से काबिज काश्त है जो नक्शा परिशिष्ट-अ से साबित है परन्तु वर्तमान लटठा नक्शा ट्रेस में तरमीम गलत अंकित कर दी गई जिस वजह से अपीलान्ट एवं रेस्पोजेन्ट्स के मध्य काश्त कब्जा

को लेकर भंयकर विवाद हुआ है तथा अपीलान्त को जबरन बेदखल करने के लिये आमदा है। पटवारी हल्का ने रेस्पोंडेन्टस से मिलभगत कर विवादित मौका रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय में पेश कर दी गई और उस आधार पर प्रस्तुत आवेदन को खारिज कर दिया। मूल खसरा संख्या 372 है, बाद में अलग-अलग समय में आवंटित होकर आवंटन अनुसार तरमीम की गई। अपीलान्त को आवंटन के समय डायरी व नक्शा अनुसार कब्जा सौंपा था, उसी के अनुसार काबिज है एवं मौके पर रहवासीय ढाणी व पानी का टांका बना हुआ और तारबन्दी की हुई हैं। अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों के आधार पर अपीलान्त की अपील को स्वीकार किया जाकर आदेश दिनांक 3.2.2025 को निरस्त किया जावे।

4. प्रत्युत्तर में रेस्पोंड संख्या रेस्पोंडसंख्या 1, 3 से 6, 7 व 9 से 11 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने यह कथन किया कि अपीलान्त के द्वारा हम रेस्पोंडेन्टगण के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 131, 136 राज० भू राजस्व अधिनियम के तहत अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र दिनांक 9.6.2022 को पेश करते हुए कथन किया कि ग्राम स्वरूपनगर तहसील शिव में ख०सं० 558/372 रकबा 6.4750 हैक्टर भूमि अपीलान्त की खातेदारी की स्थित है जिसके पडौस में हम रेस्पोंडेन्टगण यथा रेस्पोंड संख्या 2 का खेत ख०सं० 560/372, पश्चिम और दक्षिण की तरफ रेस्पोंड संख्या 3 व 4 का खसरा संख्या 567/372 व रेस्पोंड संख्या 5 से 12 का खेत ख०सं० 556/372 आया हुआ है। अपीलान्त अपनी उक्त खातेदारी भूमि जो कि उन्हें आवंटित शुदा है, जिसकी पट्टा डायरी व नक्शा प्रति वक्त आवंटन के समय अपीलान्त को जारी की थी तथा आवंटन के अनुसार भौतिक कब्जा दिलाया गया था। मगर बाद में रेस्पोंडेन्ट्स यानि सेढा पडौसियों ने माठ को तोड़ दिया तथा तरमीम अनुसार हुए कब्जा काश्त को भी बदल दिया, जिससे व्यथित होकर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तरमीम दुरुस्ती हेतु आवेदन पेश किया था।
5. रेस्पोंडेन्टस के अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि अपीलान्त के द्वारा पेश उक्त आवेदन को अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया जिस पर हम रेस्पोंडेन्टस की ओर से लिखित में प्रार्थना पत्र का जवाब पेश किया तथा कथन किया कि आवेदन में कल्पना एवं मनगढत के तथ्य अंकित किये हैं। उक्त खसरा संख्या 372 में से ही अपीलान्त एवं अन्य रेस्पोंडेन्टस को अलग-अलग रकबा भूमि आवंटन हुई थी तथा आवंटन के



समय ही कब्जा दे दिया था एवं राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद करते हुए नामा० की पुश्त पर पृथक-पृथक तरमीम अंकित कर दी थी और वर्तमान समय में भी तरमीम एवं मौके के अनुसार कब्जा काश्त करते आ रहे हैं तथा मौके एवं रिकार्ड में की गई तरमीम में कोई अन्तर नहीं होने से अपीलान्ट की ओर से पेश उक्त तरमीम शुद्धि के आवेदन को अधीनस्थ न्यायालय ने अस्वीकार किया गया है।

6. रेस्पोंडेंट्स के अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि अपीलान्ट के द्वारा तरमीम को ऑनलाईन करते समय गलत तरमीम दर्ज की गई का कथन किया परन्तु उनके द्वारा पूर्व की सही तरमीम का नक्शा पेश नहीं किया जो नहीं किया गया था क्योंकि राजस्व रिकार्ड एवं मौके पर की गई तरमीम एक समान हो रखी थी जो सही कर रखी थी। रेस्पोंडेंट्स के द्वारा अपीलान्ट को कभी भी मौके से वेदखल करने की कोई धमकी नहीं दी गई। मात्र विप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि पर से उनके द्वारा किये गये अवैध अतिक्रमण को हटाने हेतु कहा गया और यह भी अपीलान्ट के द्वारा कहा गया कि वे लोग अपनी खातेदारी भूमि की पैमाइश करवा ले, तब अगर आपकी भूमि आयेगी तो मैं आपकी भूमि पर से अतिक्रमण हटा लूंगा। अपीलान्ट ने रेस्पोंडेंट्स की सुधारी गई भूमि को हड़पने के लिये उक्त तरमीम दुरुस्ती का प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय में पेश कर दिया गया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने स्वीकार किये जाने योग्य नहीं माना तथा उसे खारिज कर दिया गया। ऐसे में अपीलान्धीन आदेश यथावत रखे जाने योग्य हैं।

7. रेस्पोंडेंट्स के अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि मूल ख०सं० 372 के विभक्त खसरा नम्बरान की दुरुस्ती अपीलान्ट ने चाही थी परन्तु ख०सं० 372 के सभी बट्टा नम्बरान के खातेदारों को प्रार्थना पत्र में पक्षकार संयोजित नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त तहसीलदार शिव के द्वारा प्रेषित तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट अपीलान्ट के कथनों के अनुसार है जो अधीनस्थ न्यायालय के आदेशानुसार तैयार नहीं की गई थी। अपीलान्ट अपने को आवंटित भूमि से असंतुष्ट है तो आवंटन आदेश को सक्षम न्यायालय में चाराजोही करनी होगी। इस प्रकार का अनुतोष धारा 131, 136 राज० भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रदान नहीं किया जा सकता है। अपीलान्ट को उक्त तरमीम का ज्ञान प्रारम्भ से ही रहा है तथा वक्त आवंटन से काबिज हो रखा है। अपीलान्ट के द्वारा रेस्पोंडेंट्स को परेशान व हैरान करने की नियत से उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया था। अधीनस्थ न्यायालय ने दोनों पक्षों को

राजस्व अपील संख्या 67/2025 अनवान काकरसिंह बनाम उरतमसिंह बगैराह

सुनने के उपरान्त अपीलान्त के उक्त आवेदन को अस्वीकार करने का अपीलार्थीन आदेश दिनांक 3.2.2025 को पारित किया गया है जो सही एवं विधि के अनकूल व उचित रूप से खारिज किया गया है जो यथावत रखे जाने योग्य है। अतः अपीलान्त की अपील सारहीन व आधारहीन होने से खारिज की जावे एवं अपीलार्थीन आदेश दिनांक 3.2.2025 को यथावत रखा जावें।

8. हमने अपीलान्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा की गई बहस पर मनन किया एवं अपील में दर्शाये गये तथ्यों का अवलोकन किया। अपीलान्त ने अपनी अपील में अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित अपीलार्थीन आदेश के विरुद्ध प्रमुखतः यह आपत्ति की है कि उपखण्ड अधिकारी, शिव के द्वारा पारित आदेश दिनांक 3.2.2025 के सम्बन्ध में मुख्यतः यह आपत्ति की है कि वादग्रस्त ख0सं0 558/372 की राजस्व नक्शे में हुई तरमीम को गलत बताते हुए उसे दुरुस्ती किये जाने हेतु प्रकरण पेश कर उनको आवंटित हुई भूमि के आवंटन अनुसार तथा मौकें पर कब्जे काश्त के अनुसार नक्शा दुरुस्ती की मांग की गई परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार की ओर से पेश मौका रिपोर्ट को आधार मानकर व उनको युक्तियुक्त अवसर प्रदान किये बिना ही उनके आवेदन को खारिज कर दिया। अतः अपील को स्वीकार कर उक्त आदेश दिनांक 3.2.2025 को निरस्त किया जावें।

9. हमने प्रकरण का तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली, अपीलार्थीन आदेश इत्यादि का गहनता से अवलोकन किया गया। जिससे यह पाया गया कि अपीलान्त ने अपने आवेदन में ख0सं0 372 के सभी बट्टा खसरा नम्बर के खातेदारों को पक्षकार नहीं बनाया गया है। द्वितीय अपीलान्त के द्वारा अपने कब्जे काश्त वाले खसरे की भूमि की आवंटन के समय दिये गये कब्जे के अनुसार की गई तरमीम एवं वर्तमान तरमीम का तुलनात्मक प्रमाण पेश नहीं किया गया यानि पूर्व समय में नामा0 पुस्त पर की गई तरमीम और वर्तमान तरमीम में अन्तर हो, जिससे यह साबित हो जाता हो कि वह वर्तमान समय में कब्जे काश्त के अनुसार आवंटित के समय कब्जा दी गई भूमि के अनुसार ही काबिज है। पटवारी हल्का के द्वारा तैयार की गई मौका फर्द व नक्शे से ऐसा आभास होता है कि अपीलान्त को अन्य आवंटित व्यक्तियों को आवंटित समान भूमि से भिन्न दिशा दर्शाते हुए भूमि का आवंटन किया गया है और वह अन्य पड़ोसी खातेदारों के खेतों में भी अपना हक-हिस्सा रखता है और थोड़ी थोड़ी हिस्सा भूमि पर काबिज हो रखा है।

10. इसके अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायालय ने यह भी निष्कर्ष दिया है कि अपीलान्त की ओर से पेश आवेदन को स्वीकार कर लिये जाने पर अन्य पड़ोसी खातेदार की भूमि के खसरे प्रभावित होंगे और मौके पर तनाव की स्थिति पैदा होगी। ऐसा प्रस्ताव स्वीकार किये जाने में तहसीलदार की ओर से भी कोई अनुशंसा नहीं की जाना भी पत्रावली पर उपलब्ध है। ऐसे में अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा प्रकरणों का विधि के अनुरूप, मौका रिपोर्ट एवं सभी पक्षों की सुनवाई किये जाने के उपरान्त अपीलान्त के तरमीम दुरुस्ती किये जाने के आवेदन को अस्वीकार किये जाने का जो अपीलाधीन आदेश दिनांक 3.2.2025 को पारित किया गया है, वो उचित रूप से पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की गुंजाइश नहीं है। इस प्रकार उल्लेखित समस्त तथ्यों पर समग्र विवेचन, विश्लेषण एवं उभय पक्षकारान के द्वारा की गई बहस पर मनन करने के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि अपीलान्त की अपील सारहीन एवं आधारहीन होने से अस्वीकार किये जाने योग्य है।
11. अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों पर विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलान्त की अपील खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शिव के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 3.2.2025 को यथावत रखा जाता है। निर्णय आज दिनांक 6.5.26 को सरे इजलास सुनाया गया।

*me*  
6/5/26.  
(सुनिता चौधरी)  
अति० सम्भागीय आयुक्त  
जोधपुर  
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त  
जोधपुर